आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 25 (प्रति रविवार) इंदौर, 10 मार्च से 16 मार्च 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

लोकसभा चुनाव के पूर्व मतभेदों के कारण चुनाव आयुक्त को देना पड़ा इस्तीफा!

दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को होगी बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव की बेला में इकलौते निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा देना चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष उनके इस्तीफे की वजह जानना चाहता है। उधर, सूत्रों की मानें तो गोयल के कुछ मुद्दों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ मतभेद तो थे। ये अलग बात है कि अमूमन बड़े अधिकारियों के बीच इतने मतभेद तो चलते हैं रहते हैं, लेकिन छह और सात मार्च को आयोग में माहौल थोड़ा अलग महसूस किया गया। अत- फिलहाल उनके इस्तीफे की वजह आपसी मतभेद माना जा रहा है। वहीं आयोग में खाली पड़े दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। अब सवाल उठ रहा है कि निर्वाचन आयोग में 7 और 8 मार्च को ऐसा क्या हुआ कि निर्वाचन आयोग में इकलौते निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया? कुछ बहुत गंभीर बात हुई है जिसकी वजह से अपनी चार साल की सेवा को अरुण गोयल ने ठोकर मार दी। अगले चार साल में दो साल से ज्यादा गोयल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहते। बैठक से गैर हाजिर थे अरुण गोयल-आठ मार्च को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला निर्वाचन सदन आए थे। सूत्रों के मुताबिक उस मीटिंग में भी गोयल गैर हाजिर थे। सीईसी राजीव कुमार अकेले थे। उस मीटिंग में गृह

सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा में राजीव कुमार के साथ अन्य निचले पायदान के आला अधिकारी मौजूद थे। सूत्र बता रहे हैं कि पहले से चले आ रहे हल्के-फुल्के मतभेद 6-7 मार्च की रात में गहरा गए। इसी में बात कुछ ऐसी निकली कि इतनी दूर तक चली गई।

15 मार्च को होगी नए पदों पर नियुक्ति-अब सरकार निर्वाचन आयोग में खाली हुए आयुक्तों के पद 15 मार्च तक भरने की कवायद में जुटी है। अब तक एक ही निर्वाचन आयुक्त की बहाली में जुटी सरकार को आनन-फानन में दो निर्वाचन आयुक्तों की बहाली की कसरत करनी पड़ रही है। सरकार में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 6-7 अफसरों का पैनल तो पहले से ही तैयार है। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से मनोनीत एक मंत्री की चयन समिति 15 मार्च को इस बाबत बैठक करेगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव की घोषणा से पहले हो जाए। सरकार के पास इस बुलेट रफ्तार के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति इसी बुलेट रफ्तार से किए जाने पर तंज कसा था। कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसा कौन सा आसमान टूटा पड़ रहा था कि सरकार बिजली को तेजी से काम करने लगी। एक दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन इस बार अर्जेंसी कुछ अलग है और जायज भी है।

टीएमसी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की सूची

पूर्व क्रिकेटर पठान, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ को उतारा मैदान में

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जन गर्जन सभा रैली के साथ लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। इस रैली में पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की लिफ्ट भी जारी की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने बहरमपुर से पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान (2007 में टी20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं) को उम्मीदवार बनाया है। यूसुफ पठान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा और कृष्णा नगर लोकसभा सीट से महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने कूचबिहार लोकसभा सीट पर जगदीश बसुनिया को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा पार्टी ने अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर प्रकाशचिक बराई, जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट पर निर्मल च रॉय, दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर गोपाल लामा, रायगंज लोकसभा सीट पर कृष्णा कल्याणी, बालुरघाट लोकसभा सीट पर बिप्लब मित्रा, मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर प्रसून बनर्जी, मालदा दक्षिण लोकसभा सीट पर शहनाज अली राहयान, जंगीपुर लोकसभा सीट पर खलीलुर्रहमान, राणाघाट लोकसभा सीट पर मुकुटमोनी अधिकारी, बोंगाओ लोकसभा सीट पर विश्वजीत दास, बारासात लोकसभा सीट पर डॉ. काकली घोष दस्तीदार, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर अभिषेक बनर्जी, जादवपुर लोकसभा सीट पर सयानी घोष, कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट पर सुदीप बनर्जी, हावड़ा लोकसभा सीट पर प्रसून बनर्जी, उलुबेरिया लोकसभा सीट पर सजदा अहमद और हुगली लोकसभा सीट पर रचना बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। घाटल लोकसभा सीट पर दीपक अधिकारी, झारग्राम लोकसभा सीट पर कालीपदा सोरेन, मेदिनीपुर लोकसभा सीट पर जून मालिया, पुरिलिया लोकसभा सीट पर शांतिराम महतो, बांकुरा लोकसभा सीट पर अरूप चक्रवर्ती, बर्धमान पश्चिम लोकसभा सीट पर डॉ. सरमिला सरकार, दुर्गापुर लोकसभा सीट पर कीर्ति आजाद (1983 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे), आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा, बोलपुर लोकसभा सीट पर असित कुमार मल, बीरभूम लोकसभा सीट पर शताब्दी रॉय, बिष्णुपुर लोकसभा सीट पर सुजाता खान, आरामबाग लोकसभा सीट पर मिताली बाग, कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट पर माला रॉय, बराकपुर लोकसभा सीट पर पार्थ भौमिक, हुगली लोकसभा सीट पर सुपरस्टार अभिनेत्री रचना बनर्जी, बशीरहाट लोकसभा सीट पर हाजी नुरुल इस्लाम और तमलुक लोकसभा सीट पर गायक देबांशु भट्टाचार्जी को उम्मीदवार बनाया है।

सांसद बृजेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल

चंडीगढ़। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बृजेंद्र सिंह और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होंगे। बीरेंद्र सिंह 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट दिलाया था।

जानकारी के अनुसार बृजेंद्र सिंह भाजपा की टिकट कटने की संभावना मानी जा रही थी। जजपा के साथ गठबंधन जारी रखने पर बीरेंद्र और बृजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ने का एलान किया था। भाजपा ने जजपा को एनडीए में शामिल किया है। भाजपा ने हरियाणा में जजपा के साथ सीट को लेकर कोई एलान नहीं किया है। भाजपा की टिकट को लेकर कोर कमेटी की एक बैठक रविवार देर शाम होने की संभावना है। इसमें भाजपा कुछ सीट पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सूत्रों के अनुसार बृजेंद्र सिंह सीट को लेकर आश्वस्त नहीं थे। भाजपा के आंतरिक सर्वे में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद हिसार लोकसभा से पूर्व वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ,पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई , डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को उतारने की तैयारी चल रही थी।

10 साल बाद कांग्रेस में वापसी-बीरेंद्र सिंह ने 2014 में कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद भाजपा ने राज्यसभा सदस्य बनाकर उन्हें केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया था। उनकी पत्नी प्रेमलता को उचाना सीट से विधायक बनाया।

संपादकीय

कांग्रेस मुक्त भारत करते-करते भाजपा का कांग्रेसमय हो जाना

राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं होता। आज जो सरकार में हैं कल उन्हें विपक्ष में भी बैठना पड़ सकता है और जो सरकार बनाने की सोच तक नहीं रखते उन्हें जनता-जनार्दन सत्ता की बागडोर सौंप शासन करने का हुक्म सुना देती है। बहरहाल यहां हम जनता के फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के बीच वर्तमान में जो घट रहा है, यहां उस पर मंथन करने और नतीजा निकालने का प्रयास किया गया है। दरअसल वर्तमान में ऐसे सियासी हादसे नजरों के सामने से गुजरे हैं, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि अब राजनीतिक दलों के अपने कोई सिद्धांत भी काम कर रहे हैं और उनकी अपनी कोई सुचिता भी बची हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की शपथ ली वही अपनी पार्टी को कांग्रेसमय करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2013 में जब लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की अभियान समिति के प्रमुख बनाए गए तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान कर तमाम सोये हुए नेताओं को जगा दिया था। इस कथित युद्धघोष ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सत्ता पर काबिज होने का मंत्र दे दिया था। इसके साथ ही भाजपा ने जहां लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर सरकार बनाने में सफलता अर्जित की वहीं राज्य दर राज्य कांग्रेस को उखाड़ फेंकने में भी वह कामयाब होती दिखी है। भाजपा की इस मुहिम में कौन कितना सहभागी बना यह भी अलग बात है, क्योंकि इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप के जो अलग-अलग दौर चले हैं, उसमें भी सच्चाई तलाशने और किसी परिणाम तक पहुंचने में खासा समय लग सकता है। वैसे कहा यही जाता है और काफी हद तक सही भी यही है कि जहां आग होती है वहीं धुंआ उठता है। कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम बहुत तेजी से चली लेकिन कब यह कांग्रेसमय भाजपा में तब्दील हो गई, खुद पार्टी नेताओं को इसका एहसास तक नहीं हुआ। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा सचमुच कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है या खुद को कांग्रेस जैसा बनाने में लगी हुई है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अल्पसंख्यकों के साथ तुष्टिकरण का जो खेल खेला उसने उन्हें रसातल पर पहुंचा दिया है, जैसा कि भाजपा दावा भी करती है। इसी तर्ज पर पिछले एक दशक से भाजपा ने बहुसंख्यक तुष्टिकरण का खेल खेलना शुरु कर दिया है। इसका परिणाम भी अब साफ देखने को मिलने लगा है। कांग्रेस की रणनीति जम गई इसलिए भाजपा नेतृत्व आंख बंद कर कांग्रेस के कथित कद्दावर नेताओं से लेकर छोटे-मोटे कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में एंट्री करवाने के लिए जी-जान से जुटी हुई है। इस मुहिम में यह भी नहीं देखा जा रहा है कि भाजपा में जिन कांग्रेस नेताओं को शामिल किया जा रहा है वो खुद अपने क्षेत्र में कितना प्रभाव रखते हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि ये अवसरवादी दल-बदलु नेता यदि इतना ही प्रभाव रखते तो क्या वो खुद अपने दम पर चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा तक नहीं पहुंच गए होते। इनका अपना राजनीतिक केरियर पहले ही समाप्त प्रायः हो गया है और येन-केन-प्रकारेण ये खुद को नेता साबित करने में जोड़-तोड़ कर रहे हैं। अब चूंकि कांग्रेस नेतृत्व इनकी हकीकत जान चुका है अतः ऐसे नेताओं पर जमीनी स्तर पर कार्य करने का दबाव भी पड़ा है, जिस कारण ये बगलें झांकते नजर आए हैं। ऐसे में ये दल-बदल कर शर्म भी महसूस नहीं कर रहे हैं। जब ये मुखौटा बदल जनता के बीच जाते हैं तो मतदाता खुद इनके मुंह में कहता दिखता है, कि शर्म तुमको मगर आती नहीं, जो यहां यूं चले आते हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पार्टी के मूल सिद्धांत को प्रमाणित करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने कथित नेता व कुछ कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले यूं पार्टी छोड़ अन्य दलों का दामन थामते नजर आ रहे हैं जैसे कि कोई पानी का जहाज डूब रहा हो और उसके अंदर रहने वाले चूहे जान बचाने के उपक्रम में समंदर में ही कूदे चले जा रहे हों। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करना स्वयं भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है।

इंडिया गठबन्धन की उलझनों से भाजपा की राह आसान

ललित गर्ग

इंडिया गठबन्धन लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए में नये दलों के जुड़ने की खबरों से उसके बड़े लक्ष्य के साथ जीत की राह आसान होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निश्चित किया है। भाजपा जहां इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुराने सहयोगियों को फिर से साध रही है तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने पर भी पार्टी का जोर है और वह इसमें बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर रही है। ओडिशा में बीजेडी और आंध्र में टीडीपी से गठबंधन पक्का माना जा रहा है। त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा भी अब भाजपा सरकार में शामिल हो गया है। भाजपा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चुनावी समीकरण सेट करने एवं विभिन्न दलों को एनडीए में शामिल करने की रणनीति में जुटी है। भाजपा ने अभी अनेक प्रांतों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, ताकि दूसरे दलों के एनडीए में शामिल करने एवं उनसे सीटों के समीकरण को सेट करने के दरवाजे खुले रहे। निश्चित रूप से भाजपा की यह मजबूत होती स्थिति विपक्ष की एकता के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती क्योंकि इंडिया गठबन्धन विभिन्न मजबूत क्षेत्रीय दलों का ही गठबन्धन माना जाता है जिसमें कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों में उतना दम नहीं है, या अनेक मजबूत दल एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं या उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा करके इंडिया गठबन्धन की सांसें छीन ली है। इन नये गठजोड़ों से बनते राजनीतिक परिदृश्य इंडिया गठबन्धन के लिये चिन्ता का कारण है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होंगे। ऐसी संभावनाएं हैं कि भाजपा शारदार एवं ऐतिहासिक जीत को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर सक्रिय है। नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि इन चुनावों के परिणाम उनके 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करें। इसलिये भाजपा विभिन्न दलों को एनडीए में शामिल करने के जोड़-तोड़ में लगी है। इस चुनाव को लेकर चुनावी गठबंधनों का दौर चल रहा है। राजनीतिक दल चुनावी गठबंधनों और सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में क्षेत्रीय दलों को जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ खड़ा है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भी कुछ राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात बना ली है। कुछ पर अब भी बात चल रही है। भाजपा ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे। कुछ ऐसे राज्य बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक हैं जहां से भाजपा ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। इन राज्यों के एक भी सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करने का कारण है- भाजपा की अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन या गठबंधन के दलों के साथ सीट शेयरिंग पर अब भी चल रही बातचीत में संभावनाएं तलाशने की रणनीति।

लोकसभा चुनाव सन्निकट हैं। इंडिया गठबन्धन एवं एनडीए रूठे नेताओं को मनाने, गठबंधन का गणित सेट करने और पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाकर कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हैं। भाजपा ने इन चुनावों में 'अबकी पार, 400 पार' का नारा दिया है। अब पार्टी इस नारे को चुनाव नतीजे में तब्दील करने के लिए व्यापक स्तर पर गठबंधनों की संभावनाओं को तलाश रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल और भाजपा का गठबंधन पक्का माना जा रहा है। अगर ये गठबंधन होता है तो राज्य में दोनों ही दलों को बढ़िया चुनाव परिणाम मिल सकते हैं। कारण कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी और वर्तमान में यहां की राजनीति पर नवीन पटनायक की मजबूत पकड़ बताई जाती है। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में दोनों पार्टियां 11 सालों तक गठबंधन में रहीं। इस दौरान दोनों दलों का राज्य की राजनीति पर दबदबा बना रहा। पटनायक राजनीति के महारथि है, उनको भाजपा के साथ गठबंधन करना ही पार्टी एवं राज्य की जनता के हित में प्रतीत हो रहा है।

बीजू जनता दल की पिछले 25 वर्षों से ओडिशा में सरकार है और इसके मुख्यमन्त्री श्री नवीन पटनायक इस पार्टी के एकछत्र नेता माने जाते हैं और इस दल का 2009 तक भाजपा से सहयोग था और यह एनडीए का हिस्सा था। 1998 में जब एनडीए का गठन हुआ था तो बीजू जनता दल स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसमें शामिल हुआ था। मगर 2008 में ओडिशा के कन्धमाल में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए थे जिनमें भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगे थे। उसके बाद 2009 में बीजू जनता दल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से बाहर आ गया था। अब पुनः 15 वर्ष बाद वर्ष 2024 के आम चुनाव में ही यह पुनः एनडीए में शामिल हो रहा है और श्री मोदी के नेतृत्व में राज्य को विकास की नयी ऊंचाइयां देना चाहते हैं। नवीन बाबू की वरीयता राज्य शासन पर काबिज रहना है और भाजपा का लक्ष्य केन्द्र की सरकार पर आरूढ़ रहना है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने में एक-दूसरे की सहायक हो सकती हैं। अतः इससे विपक्ष का यह विमर्श भी निस्तेज पड़ता है कि श्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश में भाजपा विरोध का समां बंधा है। मोदी के प्रभावी नेतृत्व का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रीय दल भाजपा का समर्थन करते हुए न केवल अपनी राजनीति को जीवंत रखना चाहते हैं बल्कि नया भारत-सशक्त भारत बनाने में खुद को शामिल करना चाहते हैं।

ओडिशा की ही तर्ज पर बिहार में भी नीतीश को मोदी के नेतृत्व में हित दिखाई दिया है। यही कारण है लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में राजनीतिक बदलाव करते हुए नीतीश एनडीए से जुड़ गये। इस बदलाव से राज्य में भाजपा और नीतीश कुमार को इस चुनाव में बड़ा फायदा होने की संभावनाएं है। राज्य में भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अलावा इन दलों का भी साथ है- चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (लोजपा रामविलास), चिराग के चाचा पशुपति पारस की लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। लेकिन इन दलों एवं भाजपा के बीच कई कारणों से पेंच फंसे हुए है, सीटों के बंटवारे को लेकर समझौते के तार उलझे हुए हैं, जो निकट भविष्य में सुलझ जाने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र की 48 सीटों में से करीब 32 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ सकती है, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लगभग 12 सीट और अजित पवार की एनसीपी को लगभग 4 सीटें मिल सकती हैं। राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में भाजपा के साथ शिव सेना ने चुनाव लड़ा था। भाजपा ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 23 पर जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 पर जीत दर्ज की। तब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में साथ थे। एनसीपी को 4 सीटों पर और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। उधर आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन हो सकता है। 7 मार्च को टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद गठबंधन की अटकलों को बल मिल गया है। राज्य में भाजपा, टीडीपी और जन सेना के बीच गठबंधन को लेकर बातें तय हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, टीडीपी भाजपा के लिए 6 सीटें छोड़ने पर सहमत हो गई है। विभिन्न गैर भाजपा राज्यों में भाजपा की स्थिति अनुकूल बनती जा रही है, जिससे उसका 400 सीटों के पार का लक्ष्य हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है।

इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 'घेरा डालो,डेरा डालो' आंदोलन के तहत

पोलोग्राउंड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय में आमजनता को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा

इंदौर। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी ने 'घेरा डालो,डेरा डालो'आंदोलन के तहत तीसरे चरण में पोलोग्राउंड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय पर सीजीएम श्री रींकेश कुमार वैश्य जी को ज्ञापन सौंपा।

शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह यादव ज्ञापन के माध्यम से कहा की झोनों पर सहायक इंजिनियर बिजली के बिलों में सुधार कर देते थे व इसका 12 दिन में निराकरण हो जाता था। अब उर्जा विभाग ने सहायक इंजिनियर से अधिकार लेकर अधीक्षक यंत्री के द्वारा ही अनुशंसा किये जाने की व्यवस्था कर दी है। अब उपभोक्ता आवेदन करते है तो ए.ई. पहले कार्यपालन यंत्री को आवेदन भेजता है कार्यपालन यंत्री फिर अधीक्षण यंत्री के यहां आवेदन भेजता है अधीक्षण यंत्री शिकायत बिल को देखने के बाद निर्णय लेता है कि,बिल की जांच करना है या नही इस पुरी प्रकिया में कई महीने लग जाते है जिससे आम उपभोक्ता परेशान है शहर के 32 कार्यालयों पर हर महीने ढाई हजार से अधिक शिकायते आ रही है औसत हर महिने 70-80 हजार के करीब फाईले बन रही है और निराकरण कुछ भी नही हो रहा है बिल

सुधार का अधिकार झोन स्तर पर किया जाये साथ ही स्मार्ट मीटरों का जो बिजली का बिल मोबाईल पर उपभोक्ताओं के पास पहुंचना चाहिये वह रीडिंग वाला बिल उपभोक्ताओं के पास नही पहुंच रहा है केवल राशी का बिल ही आ रहा है जिसमें रीडिंग नही दर्शाई जा रही है। साथ ही उपभोक्ता को पहले किश्तों में बिल भरने की पात्रता थी वह भी किश्तों में बिल नही भरे जा रहे है साथ ही विद्युत मंडल द्वारा कई सालों से नये मीटर के नये खेल कर आम उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है हालात यह है कि,कंपनी नये मीटर के नाम पर मुहिम शुरू करती है वे सभी घरों में लगे है उससे पहले ही और नया मीटर आ जाता है जिन इलेक्ट्रानिक मीटरों को तमाम कस्मों वादों के साथ घरों की दीवारों पर लगाया जाता है वे मीटर कंपनी द्वारा ही जल्दी ही नाकार बता दिये जाते है उपभोक्ताओं से कहा जाता है कि,स्मार्ट मीटर आ गया है बीते कुछ सालों से इन्हे लगाने की मुहिम चल रही है और कई घरों में लगा भी दिये है इसी बीच और ज्यादा स्मार्ट मीटर आ गये है इसमें दो तरह की तकनीकि बताई जा रही है। पहली प्री-पेड मीटर और दुसरी डिस्कनेक्शन बार बार मीटर बदलने से आम उपभोक्ता भी परेशान है उपभोक्ताओं की शिकायत है पहले हमारा बिजली का बिल कम आता था अब नये नये तकनीकि के मीटर लगाये जाने से हमारा बिजली का बिल तिगना चौगुना आ रहा है जो हम भरने में सक्षम नही है बिजली हम कम जलाते है उसके बावजुद भी हमारा बिल ज्यादा आ रहा है और इन्हे सुधारा भी नही जा रहा है। वही शहर के विभीन्न क्षेत्रों मे बिजली का वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है जिससे घरेलु टीवी फ्रिज व अन्य विद्युत उपकरण खराब हो रही है।

मुख्यरूप से प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राकेश सिंह यादव, संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल, अभिषेक करोसिया, मिथुन यादव, यशपाल गेहलोत, संजय शुक्ला, दानिश खान, दिनेश तंवर, राजू पाल, शेख सलीम, अलीम शेख, शकील मंसूरी ठेकेदार, राजेश जायसवाल, सचिन पंवार, फरीद खान, गोलूखा, सचिन कुमार, कमल बघेल, शाहरूख खान, मुरलीधर मंटागे, भीमराव सरकार, संजय यादव, सुनील बेनवंशी, लिलाधर मर्टापा, स्वराज यादव, सौरभ मथेलिया, अजीत सिंह ठाकुर, लक्ष्मण खत्री, विनोद वर्मा, पी.के.उपाध्याय, महेंद्र यादव आदि कांग्रेसजन मौजूद थे।

मंत्री श्रीमती गौर ने किया पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण

इन्दौर। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने रविवार को इंदौर जिले के तेजाजी नगर चौराहे असराबद खुर्द पर स्थित प्रदेश के पहले 500 सीटर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने छात्रावास में आवश्यक सुविधाओं के अभाव को देखकर नाराजगी व्यक्त की और मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि वह सप्ताह में एक बार आकर छात्रावास की व्यवस्थाओं को देखेंगे।

इस दौरान मंत्री श्रीमती गौर ने छात्रावास में रह रही पिछड़ा वर्ग की छात्राओं से बात कर उनकी समस्याओं को सुना। छात्राओं ने मेस व्यवस्था में सुधार करने , छात्रावास में सीसीटीवी लगाने , गीजर लगाने , आरओ वाटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने और कमरों की टूटी खिड़कियों के सुधार एवं खिड़कियों में जाली लगाने की मांग की। इस पर राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आयुक्त श्री सौरभ सुमन से एक सप्ताह के अंदर सभी जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने हॉस्टल में नियमित मेस संचालित करने, सीसीटीवी कैमरे, जिम चालू करवाने, हर फ्लोर पर आरओ वाटर एवं गीजर लगवाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा सहित अन्य सुविधाओं पर भी अब विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और जीवन में सफल हों, आपके लिए जरूरी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, इंदौर सिटी चेप्टर के चुनाव सम्पन्न

इंदौर। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, इंदौर सिटी चेप्टर ने नई कार्यकारिणी के चुनाव के साथ अपनी चुनावी प्रक्रिया समाप्त कर दी। एसोसिएशन ने इंदौर चैप्टर के लिए 2024-25 के लिए चुनाव कराया जिसमे डॉ राकेश शिवहरे अध्यक्ष व, डॉ अक्षय शर्मा सचिव चुने गए। डॉ राम मोहन शुक्ला सह सचिव व डॉ संजय महाजन को कोषाध्यक्ष चुना गया । डॉ अनिल डोंगरे, डॉ अपूर्व चौधरी, डॉ मनोज केला, डॉ अद्वैत प्रकाश, डॉ अमित कटलाना, डॉ अंकित चोरमा , डॉ राजीव जैन , डॉ प्रणव मंडोवरा, डॉ अभय भर्माने, डॉ मोहित गंगवाल को नए कार्यकारी निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया।

सात महीने भी नहीं चली राजकोट उड़ान, कंपनी ने बंद की बुकिंग

21 अगस्त 2023 को सूरत और राजकोट के लिए सीधी विमान सेवा हुई थी शुरू

इंदौर। गुजरात के प्रमुख व्यापारिक शहरों राजकोट और सूरत के लिए 21 अगस्त 2023 को सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई थी। इंदौर से राजकोट की सीधी उड़ान को विमान कंपनी इंडिगो बंद करने जा रही है। कंपनी ने 31 मार्च से राजकोट की बुकिंग बंद कर दी है। इस उड़ान का संचालन सात माह भी नहीं चल सका। यात्रियों की कमी और अन्य रूट पर विमानों की आवश्यकता की वजह से विमान कंपनी ने उड़ान को बंद करने का निर्णय लिया है।

गुजरात के राजकोट समेत पूरे सौराष्ट्र के लोगों के लिए इंदौर से सीधी विमान सेवा विगत वर्ष शुरू की गई थी। इसकी शुरूआत व्यापारियों और पर्यटकों को ध्यान में रखकर की गई। इंदौर और आसपास के व्यापारी कपड़े, हीरे, हार्डवेयर और अन्य मैन्युफेक्चरिंग के लिए राजकोट जाते हैं। मगर शुरूआत से ही इस उड़ान को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे थे।

मूंगफली एवं सोयाबीन तेल की गुणवत्ता में संदेह पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही

लगभग 8 लाख रुपए कीमत की 5174 लीटर तेल जप्त

इन्दौर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन एवं अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा शनिवार रात शहर के पालदा क्षेत्र पर नमूना एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा पालदा स्थित फर्म अथर्व इंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर मानव उपभोग हेतु विक्रयार्थ फॉर्म के द्वारा तैयार किए जा रहे सोया स्टार रिफाइंड सोयाबीन तेल, पंखिड़ा ब्रांड मूंगफली तेल नाम से मूंगफली एवं सोयाबीन तेल के पैकिंग का कार्य किया जा रहा था। उक्त तेल की गुणवत्ता में संदेह के आधार पर उक्त दोनों ब्रांड के नमूने लिए गए। साथ ही परिसर में संग्रहित सोयाबीन तेल का लूज नमूना भी जांच हेतु लिया गया एवं संदेह के आधार पर उक्त दोनों ब्रांडों के तेल के स्टॉक को जप्त किया गया। जो लगभग 5174 लीटर है जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए हैं। बताया गया कि मौके पर पाई गई अनियमितताओं को लेकर सुधार हेतु सूचना नोटिस जारी किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त पालदा स्थित एक अन्य फर्म सांवरिया इंडस्ट्रीज से अंगूर ब्रांड सोयाबीन तेल एवं लूज सोयाबीन तेल के कुल दो नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिए गए हैं। सभी नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की ओर भेजा जा रहा है , जिनकी रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

लोकसभा के बाद तय होगी पचौरी, विशाल और संजय की भाजपा में भूमिका

भोपाल। मप्र कांग्रेस के तीन कद्दावर नेताओं के टूटने के बाद पार्टी को एक बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन इन नेताओं को भाजपा क्या जवाबदारी देगी, इस बारे में अभी तय नहीं हो पाया है। भाजपा के पदाधिकारियों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही सुरेश पचौरी, विशाल पटेल और संजय शुक्ला की भूमिका तय की जाएगी। हालांकि अभी भी कांग्रेस से भाजपा में आए कई नेताओं को अपना मुकाम नहीं मिल पाया है। कुछ खास नेताओं को ही पार्टी की नगर टीम में जगह मिली तो तुलसी सिलावट मंत्री और योगेश गेंदर तथा मनोज मिश्रा जैसे नेताओं को पार्षद का चुनाव लड़वाया गया। बाकी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं को अभी तक भाजपा ने कोई बड़ी जवाबदारी नहीं दी है। कल विशाल पटेल और संजय शुक्ला के पार्टी में आने के बाद तरह-तरह की चर्चाएं चलने लगीं। चूंकि दोनों ही नेता कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं, इसलिए उन्हें स्थानीय स्तर पर तो कोई पद नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों नेताओं के कद की बात की जाए तो उन्हें प्रदेश कार्यसमिति में मनोनीत किया जा सकता है। वैसे भी दोनों नेताओं को अब भाजपा की रीति-नीति सीखना होगी। भले ही संजय शुक्ला कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार में लौट आया हूं, लेकिन आज तक उन्होंने पार्टी का काम नहीं किया है। यही स्थिति विशाल पटेल की भी है। वे भी देपालपुर में ही बंधकर रह गए थे। उनके पिता जगदीश पटेल यहां से विधायक रहे हैं

और उनकी मां सुलोचना पटेल भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं।

एक तरह से उनका अभी तक का पूरा जीवन कांग्रेस में ही बीता है तो उन्हें भी भाजपा से बहुत कुछ सीखना होगा। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में शामिल किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ जवाबदारी दी जा सकती है।

भाजपाई खुश हो या न हो, लेकिन कांग्रेसी तो खुश हैं

भले ही कांग्रेस के दोनों पूर्व विधायकों के भाजपा में आने के बाद कुछ भाजपाइयों को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी हो और वे खुश नहीं हुए हो, लेकिन 1 नंबर और देपालपुर विधानसभा के कुछ कांग्रेसियों के चेहरे पर राजनीतिक चमक देखने को मिल रही है। 1 नंबर विधानसभा में संजय शुक्ला तीन महीने पहले विधायक थे। वैसे इस विधानसभा में कांग्रसे का यादव गुट हावी रहा है और यहां से यादव परिवार के स्व. रामलाल यादव उर्फ भल्लू भैया एक बार विधायक रहे हैं। हालांकि उसके पहले ललित जैन के हाथ में यह सीट थी, जिसके बीच एक बार लालचंद मित्तल विधायक रहे थे। बाद में उषा ठाकुर को यहां से लड़ाया गया था। उषा का टिकट कटने के बाद दो बार यहां से सुदर्शन गुप्ता विधायक रहे हैं। वैसे यह सीट भाजपा की ही रही, लेकिन सुदर्शन गुप्ता को हराकर संजय शुक्ला ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पिछले साल चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने यह सीट फिर से भाजपा की झोली में डाल दी। शुक्ला के भाजपा में जाने के बाद अब यहां से एक बार फिर यादव खेमा सक्रिय होगा। खैर उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां से दीपू यादव जैसे नेता अब खुलकर सामने आ सकते हैं और कांग्रेस उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई जवाबदारी दे सकती है। यही स्थिति देपालपुर विधानसभा की भी है। विशाल पटेल का परिवार लंबे समय से यहां सक्रिय है। हालांकि बीच में इस सीट से सत्यनारायण पटेल भी विधायक रहे हैं और उनके भाई राधेश्याम पटेल अभी भी यहां सक्रिय हैं। हो सकता है एक बार फिर पटेल परिवार यहां अपनी पुरानी जड़ें बाहर निकालने में कामयाब रहे। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस विरोधी काम करने का आरोप लगाकर यहां से कांग्रेस मोतीसिंह पटेल जैसे नेता को 3 महीने के लिए बाहर कर चुकी थी, लेकिन कल ही उनका निलंबन वापस ले लिया गया। यहां से मोतीसिंह भी विधायक का चुनाव लडना चाहते थे, लेकिन विशाल पटेल के आगे उनकी नहीं चली। पटेल परिवार के सक्रिय हो जाने के बाद अब यहां से भाजपा के विधायक मनोज पटेल के लिए आगामी चुनाव में संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि तब तक विशाल अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे कल ऊपरी तौर पर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपाई खुश तो दिखे, लेकिन पटेल और शुक्ला जैसे कद्दावर नेताओं के भाजपा में आने के बाद कइयों के माथे पर अपने राजनीतिक भविष्य के लिए चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं।

सीएम डॉ. यादव की सौगात मप्र में श्रमिकों की मजदूरी हुई सात गुना

पीएम ने 9811 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन

जबलपुर/ ग्वालियर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ग्वालियर-जबलपुर एयरपोर्ट समेत 9811 करोड़ की 14 अन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास किया। ग्वालियर के एयर टर्मिनल को 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। वहीं जबलपुर की डुमना एयरपोर्ट की खूबसूरत इमारत भी जनता के लिए खुल गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। इसलिए 10 साल से गरीब मजदूरों की जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उसको बढ़ा रहे हैं। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 रुपये थी इसे अब 11450 करने की घोषणा करते हैं। अर्धकुशल श्रमिक की 1764 थी इसे बढ़ाकर के 12446 की जाती है। खेती करने वाले मजदूर की मजदूरी 1396 रुपये थी, अब उनको 9160 की जाती है।

मोहन यादव ने कहा कि मजदूरी छोडने वाले मजदूरों को भी संबल योजना में शामिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2.0 के अंतर्गत 30,591 श्रमिक परिवारों को 678 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण करने के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों की भी सौगात दी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के मौसम में पहले की सरकार में बैठे लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। साथ ही सांसद में भी रेलवे की नई घोषणाएं कर देते थे। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 2019 में भी हमने शिलान्यास किए थे वे चुनाव के लिए नहीं किए। उसका हम लोकार्पण कर चुके हैं।

संबल योजना के तहत बढ़ाई गई राशि–पेपर हॉकर्स, डिलीवरी कर्मी जैसी प्रायवेट कंपनियों के सामान को सप्लाय करने वाले जैसे सभी लोगों को अब संबल योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से मृत्यु या विकलांगता के दौरान दी जाने वाली 1 लाख की राशि भी अब 4 लाख की सहायता दी जाएगी।

इस श्रेणी के सभी लोगों को सम्बल बन कर सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। सीएम ने कहा कि मजदूरों को 50 प्रतिशत लागत पर ई-स्कूटर खरीदता है तो उसको भी 40 हजार तक निशुल्क मदद की घोषणा की जाती है।

करप्शन, कर्ज और क्राइम की सरकार की मंत्रालय में लगाई ये सरकारी आग है–जीतू पटवारी

आग वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच के झगड़े का परिणाम–उमंग सिंघार

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन में लगी आग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा सरकार से पूछा है कि पांच बार लगातार वल्लभ भवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आग लगाई है इसका दोषी कौन है? कौन सी फाइल जली? कौन से विभाग की जली एवम आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

श्री पटवारी एवम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेसजनों के साथ वल्लभ भवन पहुंचे और उन्होंने आग लगने के कारणों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली, अधिकारियों का जवाब संतोषजनक न मिलने पर श्री पटवारी और श्री सिंघार कांग्रेसियों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए।

श्री पटवारी ने कहा कि आग लगी है और पांच घंटे बाद भी बुझ नही पाई इसलिए हमें आना पड़ा। ये आग भारतीय जनता पार्टी की करप्शन, कर्ज और क्राइम की सरकार द्वारा लगाई गई सरकारी आग है, यह भ्रष्टाचार के पाप को छुपाने की आग है। वल्लभ भवन में लगी आग करप्शन, कर्ज़ और क्राइम में व्यस्त सरकार के कारनामों को मिटाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। हर चुनाव के पहले मंत्रालय में आग लगना और करोड़ों के भ्रष्टाचार के दस्तावेज ख़ाक होना संयोग नहीं प्रयोग है।

मप्र विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सिंघार ने कहा कि आग वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच के झगड़े का परिणाम है, भाजपा का अंदरूनी झगडा वल्लभ भवन की आग के रूप में सामने आ रहा है, इससे जनता का ही नुकसान है, आखिर फायर सेफ्टी सिस्टम ऑडिट क्यों नही किया गया, इसका जवाब भाजपा क्यों नही देती।

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की विशेष रणनीति

बैगा-भारिया-सहरिया के सहारे पूरा होगा मिशन 29

भोपाल। *विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया जाए। इसके लिए भाजपा ने विशेष रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत पार्टी का पूरा फोकस हर वर्ग को साधने पर है। खासकर पार्टी विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया)के सहारे मिशन 29 को पूरा करने की रणनीति पर काम कर रही है।*

गौरतलब है कि मप्र की 29 लोकसभा सीटों में से छह सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने सुरक्षित सभी सीटों को जीता था, लेकिन पार्टी इस बार भी पूरी ताकत के साथ इन सीटों को जीतने के लिए जुटी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। 47 सुरक्षित सीटों में से 22 पर कांग्रेस को विजय मिली। यही कारण है कि भाजपा विशेष पिछड़ी जनजाति पर भी फोकस कर रही है।

23 जिलों में बैगा, भारिया और सहरिया–प्रदेश के 23 जिले ऐसे हैं जहां बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति निवास करती है। प्रदेश में भले ही आदिवासियों के लिए 29 में से छह लोकसभा सीटें सुरक्षित हैं पर इनका प्रभाव दस से अधिक सीटों पर है। इनमें छिंदवाड़ा जिला भी शामिल है, जहां की सभी सात विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। यही एक मात्र लोकसभा क्षेत्र भी जहां कांग्रेस से नकुल नाथ सांसद हैं। धार में कांग्रेस ने पांच में से चार अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें जीतीं। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भी हार का सामना करना पड़ा। मंडला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने बढ़त बनाई। हालांकि, शहडोल और बैतूल संसदीय क्षेत्र में भाजपा आगे रही। आदिवासियों पर कांग्रेस की पकड़ को कमजोर करने के लिए शिवराज सरकार में बहुत प्रयास हुए। भाजपा संगठन ने भी पुरजोर कोशिश की। इसके बावजूद कांग्रेस की रणनीति सफल रही। पार्टी ने सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी डीएस राय सहित अन्य अधिकारियों को आदिवासियों को साधने के काम पर लगाया। इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को साथ लेकर पकड़ बनाई, जिसका लाभ पार्टी को चुनाव में मिला। अब भाजपा की नजर 23 जिलों में फैले बैगा, भारिया और सहरिया आदिवासियों पर है।

75 हजार को दिए पीएम आवास–इस वर्ग को साधने के लिए भाजपा निरंतर प्रयासरत है। इनके लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई पीएम जनमन योजना के अंतर्गत तीन वर्ष में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की तर्ज पर आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए चिन्हित डेढ़ लाख परिवारों में से पहले ही वर्ष में न केवल 86,228 आवास बनाने का लक्ष्य मिला बल्कि 75 हजार की स्वीकृति भी मिल गई। 60 हजार हितग्राहियों को पहली किस्त भी जारी हो गई। विशेष पिछड़ी जनजाति की बसाहटों में अधोसंरचना विकास के काम करने के लिए केंद्र सरक साथ लेने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ सहित अन्य योजनाओं के नियमों में छूट दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ सौ लोगों की बसाहट होने पर भी बना दी जाएगी। इसके लिए सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और पक्के आवास बनाने का काम हाथ में लिया गया है। प्रदेश में इनके तीन वर्ष के भीतर डेढ़ लाख आवास बनाए जाने हैं, जिसमें से 86 हजार 228 को लक्ष्य भी मिल गया और 75 हजार की स्वीकृति मिल गई। 60 हजार हितग्राहियों को पहली किस्त भी जारी की जा चुकी है।

देश में योजना के अंतर्गत पहला आवास भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भागचंद्र आदिवासी का बन चुका है। प्रधानमंत्री जनमन योजना में प्रति आवास लागत दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार और मजदूरी के लगभग 21 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

लघु वनोपज संघ के एमडी एक्शन मूड में, सीईओ और उत्पादन प्रभारी की ली क्लास, तीन साल का ब्यौरा मांगा

भोपाल। *लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक बिभाष ठाकुर ने अब एक्शन मूड में नजर आ रहें हैं। मंगलवार को प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र एमएफपी पार्क बरखेड़ा पठानी के सीईओ और प्रभारी प्रबंधक उत्पादन की जमकर क्लास ली। ठाकुर ने गत 3 साल में केंद्र में खरीदी गई जड़ी- बूटी समेत अन्य सामग्रियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। प्रबंध संचालक द्वारा प्रसंस्करण केंद्र में उत्पादन से संबंधित समीक्षा बैठकों में कई बिंदुओं पर उत्पादन प्रभारी प्रबंधक सुनीता अहिरवार को सुधार करने की कड़ी चेतावनी दी है।*

संघ के प्रबंध संचालक ठाकुर ने प्रशंसकरण एवं अनुसंधान केंद्र में लंबे समय से हो रही गड़बड़ियों को गंभीरता से लिया है। मंगलवार को बातचीत में ठाकुर ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि मैंने सीईओ पीजी फुलजले और उत्पादन प्रभारी प्रबंधक सुनीता अहिरवार से 3 साल में क्रय की गई सामग्रियों को बिंदुवार जानकारी मांगी है। मसलन, कितनी सामग्री, किस संस्था से और किस दर पर खरीदी की गई है ? खरीदी गई सामग्री टेंडर से परचेस किए गए हैं या फिर बिना निविदा बुलाए खरीद ली गई हैं। सभी डिटेल तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल से नई पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे गड़बड़ झाले और दलाली पर ब्रेक लगेगा। नई नीति के तहत सभी खरीदी जिला वनोपज यूनियन के अंतर्गत काम करने वाले संग्रहण कर्ताओं से की जाएगी।

4 सालों का उत्पादन रिकॉर्ड भी गायब-जानकारी में आया है कि पिछले 4 सालों गंभीर अनियमितताएं की गई। सूत्रों का कहना है कि विगत 4 सालों में लगभग 90 करोड़ रुपये कि दवाईओं का उत्पादन किया गया है। लेकिन उत्पादन का रिकॉर्ड संधारित ही नहीं किया गया है। विगत वर्षों की ख़रीदी का मिलान उत्पादन रिकॉर्ड से ही किया जा सकता है, परंतु उत्पादन रिकॉर्ड के नाम पर बिल वाउचर ही मिल रहे है। जिनका सही प्रमाणीकरण सही तरीक़े से जांच द्वारा ही किया जा सकता है।

इस संबंध में न तो पूर्व एसडीओ पर कार्यवाही की गई न ही प्रभारी एसडीओ सुनीता अहिरवार पर कार्यवाही की जा रही है। सीईओ फुलझेले द्वारा केवल एक आदेश निकाल कर इतिश्री कर ली गई है। सुनीता अहिरवार द्वारा भी बिल्डिंग मेंटेन्स, नर्सरी रखरखाव, और फर्जी लेवर दिखा कर करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला किया जा चुका है। दिलचस्प पहलू है कि अपर प्रबंध संचालक मनोज अग्रवाल के पत्र में दर्शित बिंदुओं पर जांच करने के लिये कोई कमेटी अभी तक नहीं बनी है।

तीन आईएफएस आएंगे जांच की जद में

पूर्व एसडीओ पिल्ल्ई के कार्यकाल में हुई अनियमितताएँ उस अवधि में मुख्यकार्यपालन अधिकारी रहे अफ़सरों की मिली भगत से ही संभव हुआ है। यदि एसडीओ पिल्ल्ई पर कार्यवाही हुई तो बड़े अफ़सर भी जद में आयेंगे। इसमें पूर्व सीईओ एवं सेवानिवृत आईएफएस एलएस रावत, एपीसीसीएफ विवेक जैन वर्तमान में वन विकास निगम में प्रभारी एमडी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ दिलीप कुमार पर भी चार्जशीट बन सकती है। इन तीन आईएफएस अफसर को बचाने के लिए जांच कमेटी का गठन नहीं किया जा रहा है।

कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा

भोपाल । लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग कभी भी आदर्श आचार संहिता का ऐलान कर सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी राजनीति गरमा गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने प्रत्याशियों और चुनावी रणनीति को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में समापन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस आज तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। इससे उलट भाजपा ने पिछले दिनों ही 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हद तो इस बात की हो गई है कि प्रदेश की सभी 29 सीटों में से पैनल बनाने के लिए कांग्रेस के पास एक से ज्यादा नाम भी नहीं है। अधिकांश संसदीय क्षेत्र में से कांग्रेस पार्टी ने एक-एक नाम का ही पैनल बनाया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने अपनी प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस से पहले जारी कर दी थी। अब लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति देखी जा रही है। वर्तमान लोकसभा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा के पास 28 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास एक सीट है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ कांग्रेस सांसद हैं।

मप्र के कर्मचारियों को 8 प्रतिशत डीए दे सरकार

भोपाल। केंद्रीय सरकार ने केंद्र की कर्मचारियों का डीए 1 जनवरी 2024 से चार प्रतिशत बढ़ा दिया है तथा पेंशनरों की राहत राशि भी बढ़ाने का फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 8 प्रतिशत डीए चार प्रतिशत जुलाई 2023 और 4 प्रतिशत जनवरी 2024 से देने के आदेश तत्काल जारी किए जाएं अन्यथा कर्मचारी मंच आंदोलन करने का निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले 9 माह से महंगाई भत्ते का लाभ राज्य सरकार नहीं दे रही है। इस कारण राज्य सरकार के ऊपर 9 माह का एरियार भी बकाया हो गया है। सरकार ने विधानसभा के लेखानुदान सत्र के दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए बजट का भी प्रावधान किया था। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने की घोषणा नहीं की। अब केंद्र के कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने पुन: चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारियों आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकार हो गया है। महंगाई भत्ता न मिलने से प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को प्रति माह करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने उज्जैन प्रवास के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश के कर्मचारियों का पाई-पाई का भुगतान राज्य सरकार करेगी लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को अभी तक किसी प्रकार का भी लाभ नहीं मिला है।

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जो शादी के बाद लाइमलाइट से दूर हो गईं। ये वो एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने एक्टिंग से ज्यादा अपनी शादी और घर को अहमियत दी। मगर, आज वो एक होममेकर होने के साथ-साथ एक सफल बिजनेस वुमन भी हैं। जानिए बॉलीवुड की उन हसीनाओं के बारे में, जिन्होंने शादी, घर और बच्चों को प्रायोरिटी दी।

सिल्वर स्क्रीन छोड़

होममेकर हो कर भी

करोड़ों कमाती हैं ये एक्ट्रेसेस

भाग्यश्री

'मैंने प्यार किया' से रातों-रात फेमस होने वाली भाग्यश्री ने पहली ही फिल्म के बाद अपने प्यार हिमालय

दासानी से परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। भाग्यश्री उस समय अपने करियर के पीक पर थीं। उस दौर में उन्हें कई प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए, लेकिन एक्ट्रेस ने करियर और शादी में शादी को चुना।

हालांकि, वो इस बीच 'कैद में है बुलबुल', 'पायल' और 'हमको दीवाना कर गए' जैसी फिल्मों में कैमियो रोल में दिखी हैं। लंबे समय बाद भाग्यश्री पति हिमालय के साथ स्टार प्लस के रियलिटी शो 'स्मार्ट जोड़ी' में दिखीं। भाग्यश्री एक होममेकर होने के साथ-साथ एक सोशल वर्कर हैं और कई सोशल काउज से जुड़ी हैं।

ट्विंकल खन्ना

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने भी अक्षय कुमार से शादी करने के बाद

एक्टिंग छोड़ दी। ट्विंकल ने कई इंटरव्यूज में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो एक्टिंग करियर के लिए नहीं बनी हैं। ट्विंकल के इसी बेबाक अंदाज के कारण उनकी अच्छी-खासी फैन-फॉलोइंग है। एक्टिंग करियर को छोड़ने के बाद ट्विंकल ने कई किताबें लिखी हैं, उन्हें इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल वुमन के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन के बिजनेस से जुड़ी है। उनके स्टोर का नाम 'द व्हाइट विंडो' है। उन्होंने ही विराट कोहली और अनुष्का का घर डिजाइन किया था। ट्विंकल कई मीडिया हाउसेस के लिए कॉलम भी लिखती हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 250 करोड़ है।

जेनेलिया डिसूजा

जेनेलिया डिसूजा ने भी रितेश देशमुख से शादी के बाद अपनी पर्सनल लाइफ और घर पर फोकस करने को चुना। फिल्मों में न आने के बावजूद जेनेलिया की कुल नेटवर्थ 130 करोड़ है। एक्ट्रेस एक अच्छी होम मेकर होने साथ एक सफल बिजनेस वुमन भी हैं। उनकी ज्यादातर कमाई ब्रांड इंडोर्समेंट और फिल्में प्रोड्यूस करने से होती है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में एक फूड कंपनी खोली है, जो वीगन मीट फूड प्रोडक्ट बेचती है। इसके अलावा जेनेलिया इंस्टाग्राम पर भी बहुत फेमस हैं। वो वहां भी कई ब्रैंड्स के साथ कोलैब करती हैं।

अमृता राव

फिल्म 'विवाह' से फेमस हुई एक्ट्रेस अमृता राव ने भी आर जे अनमोल से शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी। एक्टिंग करियर छोड़ने के बाद भी उनकी नेटवर्थ करीब 20 करोड़ है। वो ब्रांड इंडोर्समेंट के साथ-साथ पति अनमोल के साथ मिलकर 'कपल ऑफ थिंग्स' नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं।

बेहद अनोखी है पुलकित सम्राट और कृति खड़बंदा की लव स्टोरी

बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों पुलकित सम्राट और कृति खड़बंदा की शादी के चर्चे जोरों पर हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों 13 मार्च को शादी करने वाले हैं और इनका वेडिंग कार्ड भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पिछले कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। पहले को-स्टार..फिर दोस्त...फिर प्यार...और अब जल्द ही एक-दूसरे के हमसफर बनने को तैयार हैं। चलिए आपको बताते हैं इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा।

पुलकित और कृति की लव स्टोरी

रिपोर्ट्स की मानें तो पुलकित और कृति की मुलाकात फिल्म पागलपंती के सेट पर हुई थी। दोनों लगभग 5 सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिल्म पागलपंती के प्रमोशन के दौरान ही दोनों की नजदीकियों की खबरें सामने आने लगी थीं। खबरों की मानें तो 2019 में दोस्ती की शुरुआत होने के बाद लॉकडाउन के वक्त दोनों ने एक-दूसरे को अच्छे से जाना और समझा और फिर दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। कृति और पुलकित दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर जमकर प्यार लुटाते हैं।

दोनों की खूबसूरत फोटोज और प्यारे कैप्शन अक्सर फैंस का दिल जीतते हैं। ये दोनों खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं।

एक कहावत है कि जो पात्र खाली रहता है उसी पात्र में ही वस्तुएँ डाली जाती हैं भरे हुए पात्र में कोई भी वस्तु नहीं डाली जा सकती इसी प्रकार सीखने को तैयार मस्तिष्क ही

अन्य चीज़ों को ग्रहण कर सकता है अहंकार वश खुद को महान बताने वाले मष्तिष्क अंततः खाली ही पाए जाते हैं।

जीवन के लिए जरूरी है हमेशा सीखने को तैयार रहें

बातों को सुनें और समझें

ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे उत्तर देने के लिए सुनते हैं। एक अच्छा श्रोता होना बहुत कठिन है परन्तु यह व्यक्तित्व विकास का एक अहम स्टेप है। जब भी कोई आपसे बात करे, ध्यान से उनकी बातों को सुनें और समझें और अपना पूरा ध्यान उनकी बातों पर रखें। सीधी आँखों से ध्यान दें और इधर-उधर की बातों पर ध्यान ना दें।

काबिलियत

अपनी काबिलियत पर कभी भी शक ना कीजिये और हमेशा अपने से स्वयं कहें, मैं कर सकता हूँ, यह कार्य मेरे लिए है। सफलता से जुडी प्रेरक और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ें इससे जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि हम जैसे विचारों तथा साहित्यों के साथ रहते हैं हमारी मानसिकता भी वैसे ही बनती जाती है। किसी कवि ने बहुत खूब कहा है की अगर आप मानते हो की आप उड़ सकते हो तो आप जरुर उड़ोगे। जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसकी चाबी है अपने ऊपर विश्वास रखना। अपने ऊपर विश्वास रखना पहला कदम है अपने व्यक्तित्व विकास के लिए।

खुश

ये कोई नहीं बताता। खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है की आपके पास जो कुछ भी जितना भी है उसके लिए उस ऊपरवाले को धन्यवाद दें क्योंकि दुनियाँ में अरबों लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना भी नसीब नहीं हुआ। दुनियाँ की हर चीज में खुशी देखने के लिए प्रयास करें। दूसरों के साथ हँसे पर दूसरों पर कभी भी ना हँसे। व्यक्ति की हमेशा सराहना की जाती है। हँसना अच्छे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है।

विश्वास

इससे आपके विषय में बहुत कुछ पता चलता है। हर चीज चाहे वह आपका खाने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बात करने का हो या बैठने का तरीका सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से जुडा है। जब भी बैठें सभी मुश्किलों को भूल कर आराम से बैठें और जब भी आप किसी से बात करें आंख से आंख मिला कर बात करें।

सकारात्मक सोच

सभी जगह सकारात्मक सोच का होना अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे सोचने का तरिका यह तय करता है कि हम अपना कार्य किस प्रकार और किस हद तक पूरा कर सकेंगे। सकारात्मक विचारों से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व को बढ़ाता है। जीवन में कई प्रकार की ऊँची-नीची परिस्तिथियाँ आती हैं परन्तु एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा सही नज़र से सही रास्ते को देखता है।

नए लोग

ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलना और अलग-अलग प्रकार के लोगों से मिलना जीवन के एक नये स्तर पर जाना है। इससे जीवन में संस्कृति और जीवन शैली से जुडी चीजों के विषय में बहुत कुछ सिखने को मिलता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है।

ईमानदार और वफादार बनें

कभी भी किसी को धोखा ना दें और भरोसा ना तोड़ें। आपके चाहने वाले आपकी सराहना करेंगे अगर आप ईमानदारी से रहेंगे तो। जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है अगर एक बार वह विश्वास टूटा तो भरोसा करना मुश्किल हो जायेगा।

मन

बल्कि इन मुद्दों में सबसे पहले शरीर पर कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि एक अच्छे शरीर में एक अच्छा मन बसता है। व्यक्तिगत विकास के लिए शारीरिक भाषा में सुधार लाना बहुत आवश्यक है।

रोज ऑफिस लेट पहुंचना है स्वभाव की समस्या

बस स्टॉप पर जैसे ही बस रुकी, नताशा ने तेज कदमों से चलकर सड़क पार कर ली। बस स्टॉप से ऑफिस की दूरी लगभग एक-डेढ़ किलोमीटर है, जो उसे रोज पैदल चलकर तय करनी होती है। इस समय सवा दस बज रहे थे। उसका ऑफिस टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे तक होता है। वह अपने को आज काफी नर्वस महसूस कर रही थी, क्योंकि वह और दिनों की अपेक्षा ज्यादा लेट थी। ऑफिस में प्रवेश करते ही मैनेजर का केबिन ठीक सामने पड़ता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, मैनेजर ने उसे घूरकर देखा और अपने साथ बैठे मिस्टर व्यास से कुछ फुसफुसाया और फिर दोनों हंस दिये। नताशा के लिए यह रोज की बात थी थोड़ा-बहुत लेट होने की उसकी पुरानी आदत है।

क्या आप भी नताशा की तरह ऑफिस में समय पर पहुंचने को ज्यादा जरूरी नहीं समझती ? आप भले ही बेहतर कर्मी के तौर पर ऑफिस में जाने जाते हों, लेकिन यदि रोज ऑफिस लेट पहुंचना आपकी आदत में शुमार हो चुका हो तो समझ जाइये कि इसका आपके करियर पर नकारात्मक असर हो सकता है। भले ही आप सुबह से इनटाइम आये अपने सहकर्मियों की तुलना में ज्यादा इंटेलीजेंट, ज्यादा बढ़िया वर्क परफॉरमेंस वाले हों तो भी याद रखें आपके लेट आने की आदत पर लगातार आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रहती है।

करियर गाइड करने वाले गुरुओं का मानना है कि जब कोई आपको अपने यहां नौकरी देता है और आपको इसके एवज में वेतन मिलता है, तो वह सबसे पहले आपसे वक्त का पाबंद होने की उम्मीद करता है, इसलिए ऑफिस वक्त पर पहुंचना आपके संस्थान और आप दोनों के हित के लिए सर्वोपरि है। यदि आप ऑफिस समय पर नहीं पहुंचते हैं तो इससे आपके बॉस को यह संकेत मिलता है कि आपको उसके समय की कोई कद्र नहीं है। ऑफिस समय पर न पहुंचने का सीधा सा मतलब है कि आप कंपनी के शैड्यूल के अनुरूप चल पाने में पूरी तरह अक्षम हैं। कोई भी संस्थान अपने यहां ऐसे किसी कर्मी को नहीं रखना चाहेगा जो उनके शैड्यूल में फिट न हो सके।

यदि आप ऑफिस 15-20 मिनट की देरी से पहुंचते हैं या एक-डेढ़ घंटा लेट जाते हैं, बात एक ही है यानी आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं। सुबह उठकर अपनी दिनचर्या, अपनी कार्य की प्राथमिकताओं की एक सूची तैयार कर लें।

फर्जी सेल डीड से प्लॉट पर किया कब्जा

13 साल पहले फजीर्वाड़ा, नायब तहसीलदार और दो साथियों पर केस दर्ज

इंदौर। *इंदौर की राजेन्द्र नगर पुलिस ने 13 साल पुराने प्लॉट पर कब्जे के मामले में एक नायब तहसीलदार और उसके दो साथियों को आरोपी बनाया है। तहसीलदार की वर्तमान पोस्टिंग देवास में है। 2011 में इंदौर में तैनाती के दौरान आरोपी तहसीलदार ने जमीन पर कब्जे को लेकर कई साजिश की। जांच के बाद डीसीपी ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। मामला 4 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर कब्जे से जुड़ा हुआ है।*

डीसीपी आदित्य मिश्रा के मुताबिक अच्युत पुत्र राजेश्वर पदमावर और उनकी पत्नी सरिता पदमावर, गोपुर कॉलोनी में रहते हैं। इन्होंने एक शिकायती आवेदन दिया था। इसमें नायब तहसीलदार योगेन्द्र उर्फ कृष्णा पुत्र श्याम सुंदर राठौर, निवासी नरेन्द्र तिवारी मार्ग, सुदामा नगर, निलेश पुत्र जगदीश भावसार, निवासी स्कीम नंबर 71 और अजय जैनकर, निवासी सुदामा नगर ई सेक्टर द्वारा उनके प्लॉट के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर पुलिस-प्रशासन के माध्यम से लगातार कब्जे की कोशिश करने का आरोप लगाया।

डीसीपी ने एसीपी के माध्यम से जांच कराई। तब फजीर्वाड़े की पुष्टि हुई। इसके बाद तीनों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने किस तरह से कोर्ट को भी गलत जानकारी देकर गुमराह किया। बता दें कि आरोपी नायब तहसीलदार बीजेपी के एक पूर्व पार्षद का भाई है।संस्था और एक बेशकीमती प्लॉट को लेकर द्वारकापुरी में शिकायत

जिस नायब तहसीलदार कृष्णा उर्फ योगेन्द्र राठौर को राजेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपी बनाया है, उसके खिलाफ पूर्व में भी शिकायत मिल चुकी है। राठौर पर रिलेक्स गार्डन के सामने एक बेशकीमती प्लॉट पर कब्जे के मामले में द्वारकापुरी पुलिस, कलेक्टर और नगर निगम को पूर्व में शिकायत की जा चुकी है। इस मामले में राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हुई। द्वारकापुरी थाने के पीछे विक्रय कर संस्था के मामले में भी पीड़ितों ने तहसीलदार और उनके साथियों के नाम से लिखित शिकायत तत्कालीन टीआई सुधीर द्विवेदी से की थी। जिसकी जांच ही नही की गई। जबकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग होने के बाद वहां निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। पूर्व में पीड़ित प्लॉट मालिकों ने अवैध कब्जे को लेकर वर्तमान में भी शिकायतें की है। लेकिन द्वारकापुरी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

राठौर ने कहा पूरी जांच होना अभी बाकी

नायब तहसीलदार राठौर ने बताया कि यह जमीन न तो मैंने ली है और ना ही बेची है। मैं उस भूमि सौदे में केवल गवाह हूं। फिर भी आधार बनाकर मुझ पर प्रथम दृष्टया केस दर्ज किया है, इस विषय में पूरी जांच होना बाकी है। साथ ही अन्य प्रकरणों मे मेरे विरुद्ध शिकायत बताई गई है, उन जमीनों से मेरा कोई संबंध नहीं है।

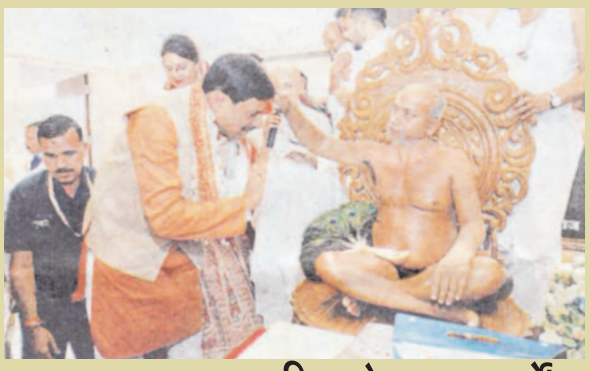

भगवान महावीर के आदर्शों को बनाएंगे पाठ्यक्रम का हिस्सा-मुख्यमंत्री

इन्दौर। गांधीनगर में नवनिर्मित सुमतिधाम के पंचकल्याणक महोत्सव में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैन संत तप-साधना से देश व समाज के कल्याण की कामना करते हैं। भगवान महावीर ने विश्व को शांति का पाठ पढाया। उनके आदर्श को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। आचार्य विशुद्ध सागर ने सत्यार्थ बोध ग्रंथ भेंट किया। आचार्यश्री की कृति वस्तुत्व महाकाव्य का विमोचन किया गया। सीएम का सम्मान सुमतिधाम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की गई। महोत्सव में सांसद वीडी शर्मा, महेंद्र सिंह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला मौजूद थे।

फर्जी अस्पताल में अयोग्य डॉक्टर कैंसर का इलाज करते मिले,किया सीले

इन्दौर। *चितावद में चल रहा फर्जी देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सील होगा। यहां जनता को गुमराह कर बीएचएमएस, बीईएमएस, बीडीएस श्रेणी के डॉक्टर खुद को विशेषज्ञ बताकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे थे।*

स्वास्थ्य विभाग अब अस्पताल संचालकों, प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर करवाएगा। नगर निगम बिल्डिंग की जांच करेगा।

कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर व एसडीएम प्रियंका चौरसिया की टीम ने 1 मार्च को जांच की थी। इसमें कई गंभीर लापरवाही मिली। वहां मौजूद अजय हार्डिया ने उन्हें बताया कि संस्था का पंजीयन नहीं है।

न कोई प्रमाण-पत्र था न एनओसी, पैथोलॉजी भी अवैध

व्यावसायिक भवन अनुमति, पॉल्यूशन कंट्रोल, हास्विन, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, फायर सेफ्टी से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं थे।

निरीक्षण में मानव अंग भी मिले, जिन्हें फार्मलीन में रखा हुआ था।

प्रबंधक ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक होने के बावजूद अपने नाम के आगे डॉक्टर और अंत में कैंसर स्पेशलिस्ट लिख रखा था।

बिना पंजीयन के पैथोलॉजी भी चलाई जा रही थी।

ये कार्रवाई होगी

डॉ. अमित मालाकर मॉनिटरिंग करेंगे। मरीजों की शिफ्टिंग के बाद सील करेंगे।

एफआईआर होगी, नगर निगम बिल्डिंग की जांच करेगा।

5 सालों में 250 नई तकनीकें विकसित करेगा आइआइटी इंदौर

उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में संस्थान ने तैयार की तीन अत्याधुनिक लैब, सीएम ने किया उद्घाटन

इन्दौर। उज्जैन में आइआइटी इंदौर के परिसर बनाने की शुरुआत हो चुकी है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में आइआइटी इंदौर ने टेक्नोलॉजी, उद्यमिता और. नवाचार के लिए तीन अत्याधुनिक रिसर्च लैब भी तैयार की हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीनों लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आइआइटी इंदौर के निदेशक नुहास भगत वर्चुअली

मौजूद है। इन प्रयोगशालाओं में करस्पेस, खगोल विज्ञान व अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और लेजर जीनियरिंग शामिल है। मेकरस्पेस प्रयोगशाला जीनियरिंग स्टूडेंट्स के स्लोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया को एक सक्षम वास्तविक परिवेश प्रदान करेगी। यह लैब स्टूडेंट्स को सिस्टम के पार्ट्स को अलग-अलग करने, उन पर शोध कर फिर उसे मूल सिस्टम बनाने के लिए सशक्त करेगी। साथ ही विद्यार्थियों के क्रिएटिव आइडिया वास्तविक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए नया सिस्टम बनाने में मदद करेगी।

लैब में लेजर आधारित जीआइ इंडेक्स प्रिंटिंग-लेजर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला से विद्यार्थियों को उद्योगों में विभिन्न अनुकूलित आवश्यकताओं के लिए लेजर सिस्टम को डिजाइन करने का अनुभव मिलेगा। इस प्रयोगशाला में लेजर आधारित जीआई इंडेक्स प्रिंटिंग रहेगी, जो कपड़ों पर बाघ लोगों प्रिंटिंग और लकड़ी की नक्काशी करने में मदद करेगी।

हाई कोर्ट में नेत्र परीक्षण शिविर

इन्दौर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और शंकर आई केयर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में हाई कोर्ट परिसर में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ जस्टिस प्रणय वर्मा ने किया। अध्यक्ष रितेश ईनाणी, सचिव भुवन गौतम विशेष रूप से मौजूद थे। डॉक्टरों की टीम ने करीब 275 वकीलों की आंखों की जांच की। हाई कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी और पुलिस कर्मियों का भी परीक्षण किया गया। कार्यकारिणी सदस्य तेजस व्यास, अरुण सिंह चौहान, धर्मेंद्र साहू, विशाल सोनी, प्रभात पांडे मौजूद थे। संचालन यशपाल राठौर ने किया और आभार शशांक शर्मा ने माना।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)